



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930

No. 82]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/PHALGUNA 8, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : रूस के मूल के या वहाँ से निर्यातित पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन (पी टी एफ ई) पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क से संबंधित निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

सं. 15/30/2008-डीजीएडी.—यतः वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30 दिसम्बर, 1999 की अधिसूचना सं. 141/1999-सी.शु. के तहत रूस (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन (पी टी एफ ई) (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

प्राधिकारी ने उक्त निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा शुरू की थी और दिनांक 7-10-2004 की अधिसूचना सं. 15/6/2003-डीजीएडी के जरिए सम्बद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी। भारत सरकार द्वारा दिनांक 18-11-2004 की अधिसूचना सं. 110/2004 के जरिए उस शुल्क को अगले पाँच वर्षों के लिए जारी रखा गया था।

2. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच तथा निर्णायक समीक्षा में शामिल उत्पाद पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन (पी टी एफ ई) है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन (पी टी एफ ई) एक कार्बनिक रसायन है और इसे सीमाशुल्क अधिनियम के उपशीर्ष सं. 390461 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन (पी टी एफ ई) के सभी रूप उत्पाद के दायरे के भीतर हैं। इस जांच के एक ऐसे उत्पाद की समीक्षा जांच होने के कारण, जिस पर पाटनरोधी शुल्क पहले से ही अधिरोपित है, विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा मूल जांच में परिभाषित किया गया है क्योंकि जांच के बाद की अवधि में उत्पाद में कोई विशेष अंतर या परिवर्तन नहीं हुआ है।

3. समीक्षा हेतु अनुरोध और उसकी शुरुआत

संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में बड़ा हिस्सा रखने वाले मै0 गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लि0, नोएडा, उत्तर प्रदेश ने रूस से पी टी एफ ई के आयातों पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा का अनुरोध करते हुए सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 के साथ पठित वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क(5) के अंतर्गत एक याचिका दायर की है।

इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर स्वयं को संतुष्ट कर लेने के बाद और इंडियन मेटल एंड फेरो अलॉयज लि0 बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में वर्ष 2006 की रिट याचिका (सिविल) सं0 16893 पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की दृष्टि से प्राधिकारी एतद्वारा लागू शुल्क को निरंतर जारी रखने की जरूरत और इस बात की समीक्षा करने के लिए पाटनरोधी नियम के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार समीक्षा की शुरुआत करते हैं कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी।

4. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश रूस है।

5. जांच अवधि

वर्तमान मध्यावधि समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अक्टूबर, 2007 से 30 सितम्बर, 2008 तक (12 माह) की है। तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और जाँच की अवधि शामिल होगी।

6. प्रक्रिया

दिनांक 7.10.2004 की अधिसूचना सं. 15/6/2003-डीजीएडी के तहत जारी किए गए अंतिम जांच परिणाम और 18.11.2004 की सी.शु. अधिसूचना सं. 110/2004-सी.शु. के तहत लगाए गए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के उपरांत प्राधिकारी एतद्वारा सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अनुसार इस बात की समीक्षा करने के लिए जांच शुरू करते हैं कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से संबद्ध देश के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों का पाटन एवं उससे होने वाली क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी। इस समीक्षा में 7.10.2004 की अधिसूचना सं. 15/6/2003-डीजीएडी (निर्णायक समीक्षा जाँच के अंतिम जाँच परिणाम) के सभी पहलू शामिल हैं। प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार उपर्युक्त पैराग्राफ 3 में यथाउल्लिखित याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग मानने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में उनका प्रमुख हिस्सा है।

7. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देश के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार भारत में उत्पाद से संबंधित माने गए ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी),
वाणिज्य विभाग,
कमरा सं. 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली- 110107

अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे दी गयी समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकती है ।

8. समय सीमा

वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध लिखित में प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर पहुँच जाने चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकॉर्ड कर सकते हैं ।

9. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना:

नियम 7 के अनुसार हितबद्ध पार्टी द्वारा प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत किया जाना संभव न हो तो उसके कारणों का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है ।

10. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं । यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या जांच में अत्यधिक बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2009

(Sunset Review)

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed against Polytetrafluoroethylene (PTFE) originating in or exported from Russia.

No. 15/30/2008-DGAD.— Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, (herein after referred to as AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally imposed vide notification No.141/1999-Customs, dated the 30th December, 1999 on import of Polytetrafluoroethylene (PTFE) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Russia (hereinafter referred to as subject country).

The Authority conducted a Sunset review of the said definitive duty and recommended continued imposition of definitive antidumping duty on import of the subject goods from the subject country vide notification No. 15/6/2003-DGAD, dated the 7th October, 2004, such duty was imposed by the Govt. of India vide Customs Notification No. 110/2004 dated 18.11.2004 for a further period of five years.

2. Product under consideration

The product under consideration in the original investigation as well as Sunset Review is Polytetrafluoroethylene (PTFE). Polytetrafluoroethylene (PTFE), is an organic chemical and has been classified under subheading no 390461 under Customs Tariff Act. All forms of Polytetrafluoroethylene (PTFE) are within the scope of the product. This being a sunset review of the product against which duty is already in force the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation, as there has been no significant development or change in the product during the period thereafter.

3. Request for Review and Initiation:

M/s. Gujarat Fluorochemicals Ltd, Noida, U.P., having major proportion of the domestic production of the subject goods, has requested under section 9A(5) of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 read with Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 for initiation of sunset review of anti dumping duties earlier imposed on imports of PTFE from Russia.

Having satisfied itself on the basis of request made by domestic industry in this regard and in view of the order of the Hon'ble Delhi High court in the matter of Indian Metal and Ferro Alloys Ltd V/s Designated Authority, Writ Petition (Civil) No. 16893 of 2006, the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of Antidumping Rules, to review the need for continued imposition of duties in force and whether the expiry of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

4. Country involved:

The country involved in this investigation is Russia.

5. Period of Investigation:

The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present mid-term review is 1st October 2007 to 30th September 2008 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2005-06, 2006-07, 2007-08 & POI.

6. Procedure:

Having decided to review the final findings issued vide Notification No. 15/6/2003-DGAD dated 07.10.2004 and final duty imposed vide Customs Notification No. 110/2004 dated 18.11.2004, the Authority hereby initiates investigations to review whether cessation of Anti Dumping duty is likely to lead to recurrence of Dumping and injury on imports of subject goods originating in or exported from subject country in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The review covers all aspects of Notification No. 15/6/2003-DGAD dated 07.10.2004 (final findings of the sunset review investigations). The Authority proposes to consider petitioner as mentioned in paragraph 3 above as domestic industry in accordance with the Rules supra as it constitutes the major proportion of the production of the subject goods in India.

7. Submission of Information:

The exporters in subject country, the governments of subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**Government of India
Ministry of Commerce and Industry
The Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110107.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

8. Time Limit:

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

9. Submission of information on Non-confidential basis:

In terms of Rule 7 the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided.

10. Inspection of public file:

Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7). In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority